साप्ताहिक

# जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 07-13 मार्च 2022, वर्ष-7, अंक-49

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

## रिकॉर्ड में 537 गाय, मौजूद आधी भी नहीं, 250 बीघा जमीन, चारा उत्पादन सिर्फ एक बीघा में

### जंगल में मिले 100 गायों के शव और कंकाल

# इंदौर में कब्रगाह बनी आदर्श गौशाला

**भोपाल/इंदौर। संवाददाता**

प्रदेश में गायों की मौत का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा है। भोपाल, शिवपुरी, रीवा और श्योपुर के बाद अब इंदौर में गायों की मौत के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल, इंदौर से 40 किमी दूर पेडमी में मां अहिल्या माता गौशाला है। पहले यह आदर्श गौशाला के तमगे को लेकर चर्चा में आई थी। अब 150 गायों की मौत के कारण सुर्खियों में है। यहां गायों के कंकाल मिले तो शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अमला, डॉक्टर और जनप्रतिनिधियों ने जायजा लिया। कलेक्टर मनीष सिंह ने गौशाला के कर्ताधर्ताओं को तलब किया। कलेक्टर ने तहसीलदार को मामले की जांच सौंपते हुए गौशाला संचालकों को ऑडिट रिपोर्ट लेकर कलेक्टर कार्यालय बुलाया। गौशाला के ट्रस्टी रजिस्टर, रसीद कट्टे व अन्य रिकॉर्ड लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला के लिए हो रहे निर्माण और सरकार द्वारा दिए गए 1.75 करोड़ के अनुदान की जांच होनी चाहिए।

गायों के बीमार होने और उनकी मौत की सूचना ट्रस्ट ने पशु चिकित्सा विभाग को नहीं दी। पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉ. अशोक बरेठिया ने बताया कि हम विभागीय जांच कर रहे हैं। शवों को डिस्पोजल करने का ट्रस्ट का तरीका सही नहीं है। हमारे डॉक्टर समय-समय पर यहां आकर जांच करते हैं, पर उन्हें भी किसी तरह की जानकारी नहीं दी।

### चारे के नाम पर खानापूर्ति

आदर्श गौशाला का दर्जा प्राप्त गौशाला के ट्रस्टियों के पास 250 बीघा जमीन है। जिसमें 1 बीघा पर ही यहां गायों के लिए चारा उगाया जा रहा है। जबकि शेष जमीन लीज पर दे दी गई है।

### आदर्श गौशाला का अवार्ड

आदर्श गौशाला का अवॉर्ड प्राप्त श्री अहिल्या माता गौशाला भी अब गायों के लिए कब्रगाह साबित हो रही है। यहां गौशाला के पास जंगल में करीब 100 से ज्यादा गायों के शव और कंकाल पड़े मिले। तीन साल पहले ही इस गौशाला को राज्य सरकार ने आदर्श गौशाला का अवार्ड दिया था।

### मृत गायों को जंगल में फेंका

पेडमी के जंगलों में गायों के शवों को दो साल से फेंका जा रहा था, जबकि इन्हें दफनाया जाना चाहिए। संसाधन और जगह होने के बाद भी शवों को फेंका जाना ट्रस्ट पर सवाल खड़े कर रहा है। पशु चिकित्सा विभाग के अफसरों ने बताया कि अब विभाग ने सभी 67 कंकालों को छह फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया है।

### 183 मवेशी गायब

गौशाला की क्षमता एक हजार गौवंश की है। यहां वर्तमान में 257 गाय, 143 बछिया, 116 बछड़े, 6 नंदी और 11 बैल मिलाकर रिकॉर्ड में 533 मवेशी होना बताया गया, जबकि हकीकत में 350 मवेशी ही मिले। ऐसे में अब तक 200 के करीब गायों की मौत होने और उनके शवों को जंगल में फेंकने की बात सामने आ रही है।

### गौशाला में सिर्फ दो-तीन कर्मचारी

गौशाला की देखरेख सुपरवाइजर अशोक करता है। ट्रस्ट में अशोक के साथ करीब 17 कर्मचारी हैं। अशोक फिलहाल हिरासत में है। इस वजह से दो दिन से किसी भी कर्मचारी की हाजिरी नहीं लगी। काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि यहां रोजाना दो से चार मजदूर ही आते हैं। सभी की हाजिरी अशोक खुद लगाता है।

### बीमार गायों को खुले में रखा

ट्रस्ट ने बीमार और अस्वस्थ गायों को खुले में छोड़ रखा है। जबकि स्वस्थ गायों के लिए दो अलग-अलग तरह के शेड बना रखे हैं। खुले में रखी बीमार व बूढ़ी गायों के खाने का भी इंतजाम समय पर नहीं किया जाता है। इस वजह से वे दम तोड़ रही हैं।

**सरकार ने दिया दो करोड़ का अनुदान** | गौशाला के रिकॉर्ड के अनुसार यहां बीमार और बुजुर्ग गायों की देखभाल के लिए छोड़ने वाले पहली बार में 2000 रुपए की रसीद कटवाते हैं। बाकी खर्च चंदे और सरकार से मिलने वाले फंड से ही चलता है। हालांकि पिछले साल ही राज्य सरकार ने इस गौशाला को दो करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया था। गौ सेवक संघ के मनोज तिवारी ने बताया कि उन्होंने यहां से 21 गाय के जियो टैग बरामद किए हैं, जिन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। गौशाला में गायों के बुरे हाल है। उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। खाने के भी इंतजाम नहीं किए गए हैं।

## गायों पर सरकार खर्च करेगी 90 करोड़

**इधर,** मध्यप्रदेश में 9 मार्च को पेश होने जा रहा वित्त वर्ष 2022-2023 का बजट पूरी तरह से चुनावी होगा। शिवराज सरकार की ज्यादातर घोषणाएं उसकी फ्लैगशिप योजनाओं पर ही होंगी। बड़ी बात यह है कि इस बार सरकार करीब दो हजार करोड़ धार्मिक योजनाओं पर खर्च कर सकती है। बजट में गायों की सेवा के लिए अलग गौ-संवर्धन पर 90 करोड़ रुपए की नई योजना लाने की तैयारी है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को वापस मिशन मोड में लिया जाएगा। कुल बजट 2 लाख 47 हजार करोड़ के आसपास होगा। बजट में नर्मदा किनारे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान रहेगा। गांवों में पीएससी-सीएससी तक लैब टेस्टिंग सुविधा का प्रावधान किया जाएगा। जल जीवन मिशन में 5,962 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 6500 करोड़ किया जाएगा। इस बार घर-घर नल के लिए 500 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे।

### बजट में गौ-संवर्धन पर होगा फोकस

## केंद्र सरकार ने खेती करवा ली, फसल कौन निकालेगा तय नहीं, काले सोने के नाम से ख्यात फसल क्षेत्र में पूरे शबाब पर

# संकट में प्रदेश के छह हजार अफीम उत्पादक किसान

**मंदसौर। संवाददाता**

देशभर में काला सोने के नाम से मशहूर अफीम की खेती कर रहे मप्र के लगभग छह हजार किसान अजीब सी स्थिति से गुजर रहे हैं। इनके खेतों में डोडे अफीम से पूरे भर गए हैं, पर उनमे चीरा नहीं लगा पा रहे हैं। आस्ट्रेलिया की तर्ज पर सीपीएस पद्धति से अफीम निकालने के लिए दिए गए पट्टों के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। इससे जहां परंपरागत खेती कर रहे किसान चीरा लगाकर रोज अफीम निकाल रहे हैं। वहीं सीपीएस पट्टे वाले किसान परेशान हैं कि अगर अफीम सूखने के बाद कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। नारकोटिक्सा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं डोडे से सीधे अफीम निकालने को लेकर अभी सरकार के पास लगभग एक माह हैं तब तक कोई न कोई निर्णय जरूर होगा।

अफीम व डोडाचूरा की तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार सीपीएस पद्धति की तरफ बढ़ रही है और इसके चलते ही मध्यप्रदेश के नीमच-मंदसौर जिले के लगभग छह हजार किसानों को इस पद्धति के तहत हरे रंग के पट्टे दिए हैं। इन किसानों की अफीम सीधे खेत से ही मशीन द्वारा निकाली जाएगी। और बची हुई फसल को रोटावेटर से नष्ट कर दिया जाएगा। अब डोडो में अफीम बनने लगी हैं और डोडे पूरे भर गए हैं।

### उलझन में किसान

किसान अपनी उपज की रखवाली में जुटे हैं कि तोते या अन्य पक्षियों ने डोडे फोड़ दिए तो फिर अफीम नीचे मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं सरकार ने अभी तक यह समय-सीमा तय नहीं की है कि डोडे कब तक खेत में ही रखने हैं। इसके अलावा नई तकनीक से अफीम निकालने वाली कंपनी डोडे तोड़कर ले जाएगी या खेतों में ही अफीम निकाली जाएगी।

### इन किसानों को मिला पट्टा

नारकोटिक्स विभाग ने सीपीएस पट्टे उन किसानों को दिए हैं, जो पिछले साल मार्फिन का प्रश 3.7 से 4.2 बीच में ही दे पाए थे। इसके अलावा दो साल में जिन औसत पूरा नहीं करने से जिनके पट्टे कटे थे उन्हें 6-6 आरी के पट्टे दिए थे। मप्र में इनकी संख्या 6 हजार है और मंदसौर जिले में 2237 हैं।

सीपीए पद्धति से मध्यप्रदेश में लगभग 6 हजार किसानों को पट्टे दिए गए हैं। इनके खेतों से अफीम निकालने के लिए दिशा-निर्देश अभी आए नहीं हैं पर किसान चिंता नहीं करें। सरकार जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है।

**संजय कुमार मौर्य,**
**उपायुक्त, नारकोटिक्स विभाग, मप्र**

### हाटपिपल्या में तीन दिवसीय कृषि जैविक मेले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा

# जैविक खेती से किसानों की बदलेगी तकदीर

भोपाल। संवाददाता

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हाटपीपल्या कृषि उपज मंडी में तीन दिवसीय कृषि जैविक मेले का शुभारम्भ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की सरकार है। प्रदेश सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जैविक खेती किसानों की तकदीर बदलेगी। किसान जैविक खेती को अधिक से अधिक अपनाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि देवास जिले में एक लाख 30 हजार हेक्टेयर भूमि पर माइक्रो उद्यम सिंचाई योजना को प्रदेश सरकार ने मंजूर किया है। इससे विकासखंड बागली और हाटपिपल्या के किसान लाभान्वित होंगे। योजना से देवास विकासखंड के भी कुछ गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने आह्वान किया कि किसान गौवंश को पालें और गोबर एवं गौ-मूत्र का प्राकृतिक खेती में उपयोग करें। किसान एफपीओ बनाएं। किसानी के साथ-साथ व्यापार भी करें। मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक कृषि का आह्वान किया है। कृषि में बढ़ते रासायनिक पदार्थों के उपयोग को देखते हुए हमें उन्नत कृषि के साथ साथ प्राकृतिक कृषि की ओर लौटने की आवश्यकता है। इस दौरान कृषि मंत्री ने कृषि जैविक मेले में लगाये गये जैविक उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया।

### किसान आत्मनिर्भर बनेंगे

कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि देवास जिले में एक लाख 30 हजार हेक्टेयर भूमि पर माइक्रो उद्यम सिंचाई योजना को प्रदेश सरकार ने मंजूर किया है। जिससे विकासखंड बागली और हाटपीपल्या के ग्रामीण लाभांवित होंगे। योजना में देवास विकासखंड के कुछ ग्राम भी लाभांवित होंगे। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार योजनाएं संचालित कर रही है। जिससे किसान आत्म निर्भर बनेंगे।

### -पर्यटन, सिंचाई, व्यापार-उद्योग में भी बढ़ेगा साझा सहयोग

# प्रदेश में इजरायल के सहयोग से बनेंगे कृषि उत्कृष्टता केंद्र

भोपाल। संवाददाता

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हाल ही में इजराइल के काउंसलेट जनरल कोबी शोशानी ने मध्यप्रदेश प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री निवास से बड़ी झील का दृश्य देख आनंदित भी हुए। काउंसलेट जनरल शोशानी ने मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुए विकास की सराहना की। उन्होंने कृषि सहित सिंचाई, उद्योग, व्यापार-वाणिज्य क्षेत्रों में इजराइल द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वर्तमान में प्रदेश में मालनपुर और मंडीदीप में इजराइल की कंपनियों के कुछ प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इजराइल के सहयोग से मध्यप्रदेश इन क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए तैयार है। इजरायल द्वारा प्राप्त सुझाव पर भी विचार कर अमल किया जाएगा। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन संजय कुमार शुक्ला उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इजराइल द्वारा प्रदेश के 2 जिलों छिंदवाड़ा और मुरैना में संतरे एवं सब्जी उत्पादन के प्रकल्प से जुड़ने की पहल की प्रशंसा की। सिंचाई क्षेत्र में भारत और इजराइल द्वारा मप्र के बुंदेलखंड अंचल में जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से दोनों देश जल प्रबंधन के अन्य संभावित क्षेत्रों में सहयोग के लिए तत्पर हैं। मप्र में औद्यागिक निवेश की संभावनाओं को भी इजराइली कम्पनियों के सहयोग से बढ़ावा दिया जाएगा।

### संतरा और सब्जी पर फोकस

मुख्यमंत्री को शोशानी ने बताया कि इजराइल का भारत में 29 कृषि उत्कृष्टता केन्द्रों में से दो केन्द्र मध्यप्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें छिंदवाड़ा में संतरा उत्पादन और मुरैना में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इजराइल में एक पखवाड़े के विशेषण पाठ्यक्रम में मध्यप्रदेश के कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी लाभान्वित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन-बेतवा परियोजना के क्रियान्वयन से बुंदेलखंड क्षेत्र का कायाकल्प होगा। प्रधानमंत्री मोदी के पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांत और इजरायल की कृषि शैली से मध्यप्रदेश प्रेरित है। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास होंगे।

### पर्यटन क्षेत्र को देंगे बढ़ावा

इजराइल के काउंसलेट जनरल ने कहा कि उन्हें भोजपुर और भीमबेटका के भ्रमण से बहुत आनंद मिला। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित ट्राइबल म्यूजियम को देखकर भी प्रसन्नता हुई। भोपाल की बड़ी झील बहुत खूबसूरत है। इजराइल के काउंसलेट जनरल ने कहा कि यह वर्ष भारत और इजराइल के 30 वर्ष के मधुर संबंधों के उत्सव का वर्ष है। इजराइल से अधिक संख्या में पर्यटक मध्यप्रदेश आएं, इसके प्रयास होंगे। मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों में वह आकर्षण है जो पूरे विश्व के पर्यटकों को यहां खींच सकता है।

# हरदा में कृषि मंत्री ने किया आह्वान, चने की बोवनी करें किसान

**भोपाल।** मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हाल ही में एक किसान के खेत में पहुंचकर उससे फसल विविधीकरण के फायदे की जानकारी ली। यह बात है हरदा जिले के मर्दानपुर की है। यहां किसान अमर सिंह ने अपने खेत में इस साल चने की बोवनी की है। उनसे गेहूं के मुकाबले चने की खेती से होने वाले फायदों की जानकारी हासिल की। मंत्री ने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले दो साल से मिर्ची और टमाटर की फसल में इस किसान को नुकसान हुआ था। इसलिए उन्होंने खुद यह सलाह दी थी कि वो चने की फसल लें। क्योंकि यह गेहूं से ज्यादा फायदा देती है। पटेल ने बताया कि आज उनकी सलाह पर सिंह के 30 एकड़ खेत में चने की फसल लहलहा रही है। कृषि मंत्री ने गांव के खेतों का जायजा लेकर किसानों से बात की। खेत में फसलों को देखा कि उसमें इस साल कैसी पैदावार की संभावना है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो पहले किसान हैं फिर मंत्री, इसलिए लोग समस्या बताएं। ताकि समाधान हो। मप्र में पहला मौका नहीं है, जब मंत्री पटेल सीधे खेतों में पहुंचे हों।

### चने की खेती में फायदा

मंत्री ने बताया कि चना प्रति एकड़ किसान को 80 हजार रुपए तक देगा। जबकि गेहूं इसका आधा पैसा ही देगा। इसलिए गेहूं की बजाए किसान चने को प्राथमिकता दें। हम किसानों को लगातार बता रहे हैं कि सरसों और चना कमाई के लिहाज से गेहूं से बेहतर है। हम समय-समय पर फसलों को बदलेंगे तो फायदा होगा। वो गेहूं और सोयाबीन की जगह दूसरी फसलों जैसे सरसों, चना या फिर बागवानी की सलाह दे रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक है। जबकि सरसों उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 11.76 फीसदी है।

### योजना के लिए 2020-21 में दो हजार करोड़ रुपए दिया था

# किसानों की कर्ज माफी के लिए बजट में नहीं होगा प्रावधान

**भोपाल।** कांग्रेस की सत्ता में वापसी का बड़ा आधार बनी किसानों की ऋण माफी योजना के लिए बजट में प्रावधान नहीं होगा। शिवराज सरकार ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पर पड़े आर्थिक भार को देखते हुए वर्ष 2020-21 में दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसमें से आठ सौ करोड़ रुपए समिति को दिए गए थे लेकिन अब प्रावधान नहीं होगा। गौरतलब है कि भाजपा कमल नाथ सरकार की कर्ज माफी योजना को किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा करार दे चुकी है। वर्ष 2021-22 में बजट में इस योजना के लिए सिर्फ प्रतीकात्मक राशि रखी गई थी। सहकारी समितियों से हर साल लगभग 25 लाख किसान कर्ज लेते हैं। कमल नाथ सरकार ने प्रदेश के 51 लाख से ज्यादा कर्जदार किसानों का कर्ज माफी योजना लागू की थी। वर्ष 2019-20 में इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कर्ज माफी के पहले चरण में चालू खाते पर पचास हजार और कालातीत खाते पर दो लाख रुपए तक कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। दूसरे चरण में चालू खाते पर एक लाख तक का कर्ज माफ होना था। यह प्रक्रिया प्रारंभ होती, उसके पहले सत्ता परिवर्तन हो गया।

### ब्याज रहित कर्ज के लिए एक हजार करोड़ का होगा प्रावधान

किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। यह राशि जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना में भी लगभग दो हजार करोड़ रुपए रखे जाएंगे। यह राशि उपार्जन करने वाली एजेंसियों को दी जाएगी। किसानों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखा जाएगा। पीएम फसल बीमा में राज्यांश मिलाने के लिए दो हजार करोड़ रखे जाएंगे।

## अब मध्य प्रदेश की उपज में नहीं चलेगा 'नागपुर'

# अब 'सतपुड़ा' के नाम से बिकेगा छिंदवाड़ा का संतरा

**देशभर में महाराष्ट्र के नागपुर की पहचान आरेंज सिटी के रूप में है। नागपुरी संतरा नाम से देश-विदेश में हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। जबकि, इस पहचान को स्थापित करने में छिंदवाड़ा के संतरा उत्पादक किसानों का अहम योगदान रहा है। लिहाजा अब अपनी मेहनत, अपनी पहचान की दिशा में काम किया जा रहा है। केंद्र की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रशासन छिंदवाड़ा के संतरे को सतपुड़ा आरेंज नाम दिया है और पहचान के लिए लोगो तैयार करवाया जा रहा है। दरअसल, छिंदवाड़ा में बीते कई वर्षों से संतरे का उत्पादन होता आ रहा है। जिले के पांढुर्ना, सौंसर और बिछुआ ब्लाक में 24 हजार 500 हेक्टेयर में संतरे के बगीचे हैं। जिनमें हर वर्ष चार लाख 49 हजार टन संतरा उत्पादित हो रहा है।**

## शिवराज सरकार ने मध्यप्रदेश के संतरे को दिया नाम और बनवाया लोगो

**छिंदवाड़ा। संवाददाता**

छिंदवाड़ा से लगे नागपुर में संतरे की देश की प्रमुख मंडी है। जिसमें छिंदवाड़ा का 60 से 70 फीसद संतरा पहुंचता है। यहीं से देश के विभिन्न राज्यों के साथ बांग्लादेश से लेकर खाड़ी देशों तक संतरा निर्यात किया जाता है। चूंकि नागपुर मंडी से संतरे का कारोबार होता है, इसलिए इसकी पहचान भी नागपुरी संतरे के नाम से स्थापित हो गई है।

### अब मिली अपनी पहचान

केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत संतरे के लिए छिंदवाड़ा जिले का चयन होने बाद अपनी पहचान मिली है। प्रशासन ने इस पहचान को स्थापित करने के लिए जिले के संतरे की सतपुड़ा आरेंज के नाम से ब्रांडिंग, पैकेजिंग के साथ बाजार में लाने की योजना बनायी है। ब्रांडिंग के लिए लोगो व क्यूआर कोड तैयार करवाया जा रहा है। कोड को स्कैन करते ही कीमत समेत संतरे की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।

### पतले छिलके का मीठा संतरा

संतरा के बगीचे के मालिक प्रकाश वाहने पिछले बीस साल से संतरा की फसल ले रहे हैं। वे बताते हैं कि छिंदवाड़ा का संतरा पतले छिलके का होता है और मिठास भरपूर होती है। गर्मी में यहां मुख्य फसल आती है। इसके लिए व्यापारियों से फसल के आरंभ में ही सौदा हो जाता है। इसके बाद फल की तुड़वाई से लेकर बेचने का काम व्यापारी ही करता है। बीते कुछ वर्षों से कई उत्पादक अब अपनी फसल सीधे बहुराष्ट्रीय कपंनियों को भी बेच रहे हैं।

छिंदवाड़ा के संतरे की गुणवत्ता जूस के लिहाज से सबसे अच्छी मानी जाती है। अब जिले में ही इसके लिए बड़े किसानों के बीच प्रसंस्करण यूनिट लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। कुछ यूनिट पहले से काम कर रही हैं, लेकिन वे उत्पादकों की नहीं हैं। अलग पहचान के लिए सतपुड़ा आरेंज नाम दिया गया है। अपनी पहचान मिलने से मार्केट में यहां के संतरे की अलग मांग और कीमत होगी।

**सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर, छिंदवाड़ा**

### देवास का किसान संतरे से लेकर गुलाब तक उगा रहा

## खेती का तरीका बदला और बन गए लखपति

**देवास।** परंपरागत खेती को छोड़ कुछ किसान आधुनिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं देवास जिले के ग्राम खोखरिया के रहने वाले धर्मपाल सिंह ठाकुर। परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक पद्धति से खेती की। अब वे 12 से 15 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। 10 लोगों को रोजगार भी दे रखा है।

जागत गांव हमार बता रहा है कि आधुनिक पद्धति खेती कर कैसे धर्मपाल ने इसे लाभ का धंधा बना लिया। धर्मपाल सिंह ठाकुर ने बताया कि कुछ वर्षों पहले तक उनका परिवार परंपरागत खेती पर निर्भर था। इसमें लागत ज्यादा और आय सीमित हुआ करती थी। उन्होंने उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। शासन की योजनाओं की जानकारी ली। चार साल पहले उद्यानिकी विभाग ने उच्च तकनीक से सब्जियों की खेती के लिए 4000 वर्ग मीटर में पॉलीहाउस का निर्माण कराया। इसमें एक साल पहले तक उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के बताए अनुसार गुलाब की खेती की। 4000 वर्ग मीटर में 40 हजार गुलाब के पौधों की ट्रांस प्लांटिंग जून-जुलाई में की गई।

**दस माह में छह लाख रुपए आमदनी**- दस महीने में ही 6 लाख रुपए की आमदनी हुई। पूरी फसल में कुल खर्च 1.50 लाख आया। इस तरह शुद्ध लाभ 4.50 लाख रुपए हुआ। इसी प्रकार 1 हेक्टेयर में 4 साल पहले संतरे के 300 पौधे रोपे थे। इससे अब सालाना 2 लाख की आय हो रही है। साथ ही वे टमाटर की खेती के साथ प्याज भंडार भी कर रहे हैं। सालाना 12-15 लाख की आय उन्हें इस तकनीक से हो रही है।

### इन तकनीक का उपयोग

सिंह ने बताया कि आधुनिक खेती के लिए वे पॉलीहाउस, करीब 4000 वर्ग मीटर, ड्रिप सिस्टम 1 हेक्टेयर, प्लास्टिक मल्चिंग 1 हेक्टेयर, वर्मी कम्पोस्ट 1, प्याज का भंडारण 50 मैट्रिक टन, यंत्रीकरण का प्रयोग पावर टिलर, पावर स्प्रेयर सहित अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं।

### कई बार हुए सम्मानित

देवास जिले के भ्रमण के दौरान तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें सम्मानित की भी किया था। साथ ही आधुनिक खेती के लिए इसी वर्ष गणतंत्र दिवस 2022 के समारोह में भी उन्हें सम्मानित किया गया है।

### खेती की आय से डेयरी फार्म भी कर दिया शुरू

धर्मपाल ने बताया कि उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से वे सदैव संपर्क में रहते हैं। वे जो भी मार्गदर्शन देते हैं, उसी अनुसार खेती में बदलाव करते हैं। खेती से हो रही आय से उन्होंने अब डेयरी फार्म भी शुरू कर दिया है। आधुनिक खेती के माध्यम से टमाटर, प्याज, लहसुन, संतरा, सीड्लेस खीरा सहित अन्य फसलों का उत्पादन भी कर रहे हैं। वे उपज को दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में भी विक्रय के लिए भेजते हैं। 10 श्रमिकों को उन्होंने रोजगार दे रखा है, जो फसलों की पैकिंग करने में मदद करते हैं।

### संदीप पाटीदार ने पहली बार की चंदन की खेती

## नीमच में संतरे के साथ ही चंदन की खेती कर रहे किसान

**नीमच। संवाददाता**

नीमच जिले की जीरन निवासी लघु कृषक संदीप पाटीदार के पास एक हेक्टेयर भूमि है। संदीप नवाचारी किसान हैं, जो सामान्य रूप से परंपरागत फसलों के साथ ही औषधीय फसलों की खेती भी करते हैं। किसान पाटीदान ने जिले में पहली बार नवाचार कर चंदन की खेती को सफल बनाया है। जिले में सबसे पहले चिया फसल को लगाने वाले दो किसानों में एक यह भी हैं। उनके यहा 0:4 हेक्टेयर भूमि में उन्होंने संतरे का बगीचा भी लगा रखा है, जो वर्तमान में सात वर्ष का है। आरंभ के वर्षों में वे खरीफ और रबी की फसल लेते रहे हैं। लेकिन बार-बार खेत की तैयारी और अन्य खर्चों को देखकर उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे कि बार-बार बोवनी न करनी पड़े और आय भी अच्छी मिले। भले ही इसमें कुछ समय लग जाए।

### गुजरात से लाए चंदन के पौधे

किसान पाटीदार ने इस बारे में सोचा और मंथन के उपरान्त चंदन पर इनकी तलाश खत्म हुई। उन्होंने चंदन की खेती के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास आरंभ किए। इस कड़ी में इनको सहयोग मिला उन किसानों का जो पूर्व से चंदन की खेती कर रहे थे। आवश्यक जानकारी मिलने के पश्चात उन्होंने गुजरात के आनंद की नर्सरी से अच्छी किस्म के 300 सड़ेद चंदन के पौधे लाकर अपने संतरे के बगीचे में संतरे की कतारों के बीच अंतरवर्ती फसल के रूप में लगाएं।

### 270 पेड़ तैयार

मेड़ का उपयोग करते हुए मेड़ पर भी चंदन के पौधे लगाए। चंदन का पौधा आंशिक परपोषी होने से इसके साथ लाल मेहंदी और केजुरीना का पौधा भी लगाया। आज इनके बगीचे में लगे चंदन के पौधे दो वर्ष के हो चुके हैं। जिनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट हो गई है और 270 पौधे वर्तमान में जीवित हैं। चंदन के पौधे 10 से 12 वर्ष में विक्रय के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे उनको अच्छी आय प्राप्त होगी।

# दुधारू पशुओं के चयन में बरतें सावधानियां

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय-भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। दुधारू पशु की खरीद में बहुत बड़ी पूंजी खर्च होती है। इनके अच्छे गुणों के ऊपर ही डेयरी व्यवसाय का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि अच्छी नस्ल और गुणवत्ता के दुधारू पशुओं से ही अधिक दुग्ध उत्पादन हासिल कर पाना संभव हो पाता है। इसलिए दुधारू पशु का चयन एवं खरीदारी करते समय अच्छी नस्ल, दोष रहित पूर्णतः स्वस्थ्य पशु, लंबे ब्यांत, हर साल बच्चा और अधिक दूध देने वाली गाय-भैंस को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे व्यवसाय में लगाई गई पूंजी से अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सके। तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है।

ऐसी गाय की पहचान के लिए उसके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चैड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर एवं मुंह-माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। अयन पूर्ण विकसित और बड़ा होना चाहिए। थनों और अयन पर पाई जाने वाली दुग्ध शिराएं जितनी उभरी और टेड़ी-मेड़ी होंगी पशु उतनाही अधिक दुधारू होगा। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार एवं आपसी दूरी समान होनी चाहिए। गाय-भैंस के पेट पर पाई जाने वाली दुग्ध शिराएं जितनी स्पष्ट, मोटी और उभरी हुई होंगी पशु उतना ही अधिक दूध देने वाला होगा। दुधारू पशु को खरीदते समय हमेशा दूसरे अथवा तीसरे ब्यांत की गाय-भैंस को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि इस दौरान दुधारू पशु अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप खुलकर दूध देने लगते हैं और यह क्रम लगभग सातवें ब्यांत तक चलता है। इसके पहले अथवा बाद में दुधारू पशु के दूध देने की क्षमता कम रहती है। दूसरे-तीसरे ब्यांत के पशु को खरीदते समय प्रयास यह होना चाहिए कि गाय-भैंस उस दौरान एक माह की ब्याई हुई हो और उसके नीचे मादा बच्चा हो। ऐसा करने से उक्त पशु के दूध देने की क्षमता का पूरा ज्ञान होने के साथ ही मादा पड़िया अथवा बछड़ी मिलने से भविष्य के लिए एक गाय-भैंस और प्राप्त हो जाती है, जो कि भविष्य की पूंजी है। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार तीन बार दोहन करके देख लें। क्योंकि व्यापारी चतुराई से काम लेते हैं और आपको पशु खरीदते सयम मात्र एक बार सुबह अथवा शाम को ही दोहन करके दिखाएंगे। ऐसा करने से आपको प्रतीत होगा कि यह पशु अधिक दूध देने वाला है, लेकिन सच्चाई यह नहीं होती है। व्यापारी एक समय का दोहन नहीं करता अथवा कम दुग्ध दोहन करता है जिससे दूध की मात्रा अयन में रह जाती है। इस कारण लगता है कि गाय-भैंस अधिक दूध देने वाली है। इसलिए दुधारू पशु की खरीदारी करते समय तीन बार लगातार दुग्ध दोहन अपने सामने अवश्य करा लेना चाहिए। कई बार व्यापारी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर दूध दोहन कराते हैं। इससे बचने के लिए जब भी दुग्ध दोहन कराए तो अपने सामने कम से कम आधा घंटा व्यापारी से बात करने में गुजार दें फिर इसके बाद ही दोहन कराएं। दुधारू पशु का चयन करते सयम उसकी सही आयु का पता लगाना आवश्यक होता है, जिससे कोई आपको पशु की आयु कम बताकर धोखा नहीं दे सके। दुधारू पशु की आयु की जांच के लिए कई तरीके अमल में लाए जाते हैं। जिन्हे खरीदते समय मौके पर अपना कर पशु की ठीक-ठीक आयु का पता लगाया जा सकता है। पशु की सही आयु का पता लगाने के लिए उसके दांतों को देखा जाता है। मुंह की निचली पंक्ति में स्थायी दांतों के चार जोड़े होते हैं। ये सभी जोड़े एक साथ नहीं निकलते हैं। दांत का पहला जोड़ा पौने दो साल की उम्र में, दूसरा जोड़ा ढाई साल की उम्र में, तीसरा जोड़ा तीन साल के अन्त में और चौथा जोड़ा चौथे साल के अन्त की उम्र में निकलता है। इस प्रकार से दांतों को देखकर नई और पुरानी गाय-भैंस की सटीक पहचान की जा सकती है। औसतन एक गाय-भैंस 20-22 वर्षों तक जीवित रहती है। गाय-भैंस की उत्पादकता उसकी उम्र के साथ-साथ घटती चली जाती है। दुधारू पशु अपने जीवन के यौवन और मध्य काल में अच्छा दुग्ध उत्पादन करता है। इसलिए दुधारू पशु का चयन करते समय उसकी उम्र की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। भैंस के सींग के छल्ले भी आयु का अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। प्रथम छल्ला सींग की जड़ पर प्रायः तीन वर्ष की आयु में बनता है। इसके बाद प्रति वर्ष एक-एक छल्ला और आता रहता है। सींग पर छल्लों की संख्या में दो जोड़ कर भैंस की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु देखने में आया है कि कुछ लालची लोग अधिक रुपया कमाने के चक्कर में दुधारू पशु खरीदार को धोखा देने के लिए रेती से छल्लों को रगड़ देते हैं। इसलिए यह विधि विश्वसनीय नहीं कही जा सकती है। दूध देने वाले दुधारू गाय-भैंस में सींग पश की नस्ल की पहचान का मुख्य चिन्ह होते हैं। यद्यपि सींग के होने या नहीं होने का पशु के दुग्ध उत्पादन की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। भैंस की मुर्रा नस्ल आज भी अपने मुड़े सींगों के कारण ही पहचानी जाती है। पशु की सेहत देख कर पशु की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। बूढ़े पशु की अस्थि संधियां कमजोर हो जाती हैं और पशु धीमी गति से चलता है। उसकी त्वचा ढीली हो जाती है और मुंह से दांत गिर जाते हैं। बूढ़े पशु की आंख के पीछे तथा कान के बीच के टेम्पोरल क्षेत्रों में गड्ढ़ा बन जाता है। इसके विपरीत युवा अवस्था की भैंसों व गायों का शरीर सुंदर, सुडौल, चुस्त, चमकदार त्वचा तथा चर्बी कम होती है। अच्छी खुराक होने पर भी बूढ़े पशु और स्वस्थ्य पशु में अंतर कर पाना संभव नहीं हो पाता है। खुले बाजार, मेलों, हाट पेंठ आदि से पशुओं को खरीदने में कभी-कभी पशु की पहचान करने में धोखा हो जाता है। अतः खरीदते समय उक्त स्थान पर यदि गर्भ की जांच करने वाला कोई जानकार या पशु चिकित्सक हो तो उससे गर्भ जांच करा लेना चाहिए। भैंस के सींगों का बारीकी से निरीक्षण कर लें की कहीं दारातीं से घिसे हुए तो नहीं हैं। त्वचा की चमक पर धोखा खाने से पहले देख लेना चाहिए कि भैंस पर चमक पैदा करने के लिए काला तेल तो नहीं चुपड़ दिया गया है। कई बार चालाक किस्म के लोग बाखरी गाय-भैंस के नीचे किसी दूसरी अनउपयोग गाय-भैंस का नवजात लवारा बांध देते हैं तथा उसे ताजी ब्याही बता कर अधिक कीमत में बेचकर धोखा दे देते है। इससे बचने के लिए बच्चे को उसकी मां के नीचे लगाकर देखना चाहिए। दूध बढ़ाने के लिए चीनी, गुलकंद, जलेबी की चासनी, ओवर फीडिंग करके भी व्यापारी दूध की मात्रा में वृद्धि करके दिखा देते हैं। अतः इसकी पहचान अनुभवी पशु पालकों के माध्यम से अथवा संभव हो तो तीन-चार दिन नजर रखकर की जा सकती है। भैंस के रंगे खुरत थाका जल लगी आंखों को सफेद कपड़े से पोछकर पता किया जा सकता है। दुधारू गाय-भैंस की खरीद करते समय अयन और थनों की बारीकी से जांच कर लेनी चाहिए जिससे थनैला बीमारी के बारे में भली प्रकार से पता चल सके। यदि थन में गांठ, सूजन आदि के लक्षण हैं तो थनैला हो सकता है। ऐसे पशु को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। दूध देने वाली गाय-भैंस की जांच हेतु उसे ढलान वाले स्थान पर पीछे का हिस्सा करके बिठाकर देखने से पता लगाया जा सकता है। कई बार व्यापारी कमजोर पशु में तथा उसके अयन में हवा भरवा देते हैं, जिससे वह हष्ट-पुष्ट, गर्भवती अथवा अधिक दूध देने वाली प्रतीत हो सके।

# अमूल दूध के दाम बढ़ने से क्या पशुपालकों को होगा फायदा

देवेंद्र सिंह
वरिष्ट पत्रकार

मार्च में अमूल ने देश भर में दूध बढ़ा दिए हैं। आठ महीने बाद दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले जुलाई, 2021 को दो रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए गए थे। पशुपालक और डेयरी किसान लगातार दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे, दूध के दाम बढ़ाने से आम लोगों का खर्च बढ़ेगा, वहीं पर पशुपालकों को इससे फायदा होगा। हरियाणा में चंडीगढ़ के खेड़ी गांव में गैर मिलावटी समाज ग्वाला गद्दी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व डेयरी संचालक मोहन सिंह आहलूवालिया दूध की बढ़ी कीमतों पर कहते हैं कि सर्दियों में दूध का उत्पादन ज्यादा होता है, जबकि खपत कम रहती है।

दरअसल, गर्मियों में दूध की आवक यानी दूध का उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन खपत बढ़ जाती है। क्योंकि गर्मियों में दूध के साथ ही दही और छाछ की मांग भी बढ़ जाती है। इसलिए गर्मियों में दूध का रेट बढ़ाया जाता है। एक जुलाई से पहले अमूल ने दिसंबर, 2019 के दाम बढ़ाए थे। पशुपालक लंबे समय से दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे थे, ऐसे में देश की सबसे बड़ी दुग्ध समिति के दाम बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) ने 27 फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि पिछले 2 वर्ष में अमूल ने अपने फ्रेश दूध की श्रेणी की कीमतों में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत का इजाफा किया है। विज्ञप्ति में आगे कहा है कि एनर्जी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और जानवरों के चारे की लागत में इजाफे के कारण दूध उत्पादन खर्च में इजाफा हुआ है, जिससे संचालन की कुल लागत में बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए अमूल ने किसानों की दूध खरीद की कीमतों में 35 रुपए से 40 रुपए किलो फैट की वृद्धि की है, जो पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा है। अमूल के साथ देश के 18500 गांवों में सहकारी मंडलियां (दुग्ध समितियां) हैं। करीब 80 डेयरी प्लांट हैं। 50 हजार करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है। अमूल आज देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। जिसे छोटे-छोटे लोगों ने मिलकर कर बनाई है। मोहन आहलूवालिया आगे कहते हैं कि अभी दूध का किसानों के लिए भी अच्छा है, ये मान के चलिए कि पिछले दस सालों में सबसे अच्छा रेट मिल रहा है। आज का रेट कॉपरेटिव में लगभग 48 रुपए और प्राइवेट में 50 रुपए प्रति लीटर रहा है, ये 6.50 फैट और 9 एसएमफ का रेट है। 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में 14.51 करोड़ गाय और 10.98 करोड़ भैंसें हैं, जबकि गौधन (गाय-बैल) की आबादी 18.25 करोड़ है। साथ ही दुधारू पशुओं (गाय-भैंस) की संख्या 12.53 करोड़ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार देश में लगभग 187.7 मिलियन टन (2018-19) दूध का उत्पादन होता है। अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर होगी। वहीं अमूल ताजा 24 रुपए प्रति 500 मिली, और अमूल शक्ति की कीमत 27 रुपए प्रति 500 मिली होगी। ये कीमतें 1 मार्च से लागू हो गई हैं। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले चार वर्षों में भारतीय डेयरी सेक्टर 6.4 फीसदी की दर से बढ़ गया है, जबकि विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन वृद्धि दर मात्र 1.7 प्रतिशत है। देश में दूध उत्पादन 2014-15 के 146.3 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2018-19 में 187.7 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन इसकी एक सच्चाई यह भी है कि दूध कारोबार से जुड़े किसानों को लिए यह सेक्टर घाटे का सौदा बनता जा रहा है। लगभग आठ करोड़ ग्रामीण परिवार दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। इनमें भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों की संख्या सबसे अधिक हैं।

# चुनौतियों से कैसे उबार पाएगा केंद्रीय बजट-2022-23

पूरी दुनिया में विकास के मामले में भारत अभी भी कई देशों के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ है। जीवन की गुणवत्ता, मानव पूंजी और मानव विकास सूचकांक की यदि बात की जाए तो भारत 189 देश में से 131वें स्थान पर है। साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 116 देशों के श्रेणी में 101वें स्थान पर है, जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है। यह बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट है कि पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी का गरीब, वंचित समुदाय और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा पर बेहद ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। वैश्विक संगठन ऑक्सफैम की इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट और आईसीई-360 सर्वेक्षण सहित कई हालिया रिपोर्टें अच्छी तरह से यह स्थापित करती हैं कि भारत में आर्थिक विकास में सुधार की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब कि समाज के गरीब वर्गों की आय कम होती जा रही है, जबकि धनी वर्गों की आय में भारी मात्र में बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि कई विशेषज्ञ बताते हैं कि कोविड महामारी के बाद से यह प्रवृति काफी तेज हो गई है लेकिन देश, इस तरह की असमानता का अनुभव पिछले कुछ दशकों से करता आ रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2016 के बाद यह साफ तौर पर देखा गया है कि लोगों को स्थिर रूप से उनकी मजदूरी नहीं मिल पाई है और बेरोजगारी की संख्या में उतरोतर इजाफा होता चला गया है। इस संदर्भ में, मौजूदा बजट से यह उम्मीद की गई थी कि सामाजिक क्षेत्र के बजट में इजाफा किया जाएगा और इसके सरकारी खर्चों में विस्तार देखने को मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र पर अधिक बजट प्रावधान और खर्च से ही मानव विकास के परिणामों में सुधार में योगदान हो सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान आर्थिक संकट के दौरान लोगों को राहत देने के साथ- साथ निजी खपत की मांग को बढ़ावा देने में भी योगदान देता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और गुणात्मक प्रभाव होता है। हालांकि, लोगों के मौजूदा संकट और उनकी मांग के बावजूद, बजट ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसा लगता है कि रोजगार-केंद्रित और समावेशी विकास पर निवेश करने के बजाए केंद्र ने इस अवसर का उपयोग अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सिर्फ प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय स्तर पर यह स्पष्ट है कि लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, सरकार ने यह घोषणा की है कि वह एक कक्षा, एक टीवी चैनल योजना का विस्तार करेगी, लेकिन सरकार को यह चाहिए था कि वह स्कूलों पर अपना आवंटन बढ़ाए ताकि स्कूलों को फिर से एक नए जोश के साथ खोला सके। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

### -पैकिंग, परिवहन और मार्केटिंग की सुविधा किसानों को मिलेगी

# गुना में नीति आयोग ने दी जैविक प्रोजेक्ट को मंजूरी

गुना। संवाददाता

आकांक्षी जिला गुना के जैविक प्रोजेक्ट को नीति आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के स्वीकृत होने के साथ ही जिले को लगभग 90 लाख रुपए की राशि मिलेगी। इससे कृषि विभाग जैविक खेती में रुचि रखने वाले किसानों का चयन कर ट्रेनिंग, उत्पादन, परिवहन और मार्केटिंग की व्यवस्था कराएगा। इससे जिले में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, तो किसानों को भी उपज के अच्छे दाम भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, जैविक उपभोक्ताओं को भी अच्छा अनाज, सब्जी और मसाले मिल सकेंगे। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। खास बात यह कि जैविक उपभोक्ताओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था भी की जाएगी।

**महंगी फसल का बढ़ेगा रकबा**- जिला प्रशासन ने आकांक्षी जिला के तहत जैविक खेती का बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैविक प्रोजेक्ट तैयार कर नीति आयोग को भेजा था। इसी क्रम में आयोग ने उक्त प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट से जिले के माइक्रो इरीगेशन (सूक्ष्म सिंचाई) के क्षेत्रफल और हाई वेल्यू क्रॉप्स (उच्च मूल्य की फसल) के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, जिससे जिले की रैंकिंग में सुधार होगा। इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है।

**प्रशिक्षण के साथ उत्पादन**- चयनित हितग्राही किसानों के यहां जैविक प्रोजेक्ट में मंजूर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण, ड्रिप, जैविक आदान सामाग्री, बायोपेस्टीसाइड, नर्सरी तैयार करने की व्यवस्था के साथ ही जैविक उत्पादों की पैकिंग, परिवहन, प्रचार-प्रसार एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। कृषकों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण भी कराया जाएगा, ताकि जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता बनी रहे। जैविक उत्पादों के नमूनों की जांच भी प्रयोगशालाओं में कराई जाएगी।

## घर तक जैविक उत्पाद पहुंचाएगा एप

प्रोजेक्ट के तहत जैविक उत्पादों जैसे सब्जी, फल, अनाज, दाल, खाद्य तेल आदि की सप्लाई जैविक उपभोक्ताओं के घर पर आर्डर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से उपभोक्ता आर्डर कर सकेंगे। कृषि विभाग के अनुसार जरूरत को देखते हुए जैविक आउटलेट खोलकर भी उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

आकांक्षी गुना जिले से नीति आयोग को जैविक प्रोजेक्ट तैयार कर भेजा गया था, जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने राशि भी मिलेगी। जैविक खेती में रुचि रखने वाले किसानों को प्रशिक्षण से लेकर उत्पादन, परिवहन, मार्केटिंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। होम डिलेवरी के साथ ही आउटलेट खोलकर उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

**फ्रेंक नोबल ए., कलेक्टर, गुना**

जिले में प्रोजेक्ट के लिए लगभग 150 कृषकों का चयन किया गया है। इन किसानों को कृषि विभाग मार्गदर्शन के साथ जैविक गतिविधियां आयोजित करेगा। इसके साथ ही जैविक उत्पादन कर मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसानों को जैविक उत्पाद का उचित मूल्य एवं जैविक उपभोक्ताओं को जैविक उत्पाद उपलब्ध कराना है।

**अशोक उपाध्याय, उपसंचालक, कृषि, गुना**

### ग्रामोदय,डीआरआई-सदगुरु की पहल

# चित्रकूट: आदिवासी गांव मोहकमगढ़ में लगा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर

**चित्रकूट।** महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि, सदुरु सेवा संघ ट्रस्ट व दीनदयाल शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आदिवासी-वनवासी ग्राम मोहकमगढ़ में नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह संयुक्त शिविर स्किल सेल एनीमिया रोग और इसके चिकित्सीय निदान पर केंद्रित रहा। कुलपति प्रो. भरत मिश्रा ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति मंगु भाई पटेल के मार्गदर्शक आह्वान पर यह स्वास्थ्य शिविर स्किल सेल एनीमिया रोग पर केंद्रित है। उन्होंने ग्रामोदय विवि द्वारा गोद लिए आदिवासी वनवासी गांव मोहकमगढ़ में स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा के मासिक शिविर में ग्रामोदय विवि की आयुर्वेद यूनिट के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए सदुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित जानकीकुंड चिकित्सालय और दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा संचालित आरोग्यधाम के चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चित्रकूट के समग्र विकास में लगे दोनों संस्थान ग्रामोदय विवि के साथ मिलकर पूरी निष्ठा व ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

## 52 लोगों की जांच

एक दिवसीय इस शिविर में ग्रामोदय विवि द्वारा गोद लिए गए गांव मोहकमगढ़ मे 52 लोगों में स्किल सेल एनीमिया रोग का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और विवि के एमबीए व डीफार्मा के विद्यार्थियों ने मोहकमगढ़ गांव में घूम घूम कर ग्रामीणों में स्किल सेल एनीमिया के प्रति जनजागृति की। शिविर में ग्रामीण विकास एवं व्यवसाय प्रबंधन संकाय के अधिष्ठाता प्रो अमरजीत सिंह व ग्रामीण विकास विभाग के अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र प्रसाद पांडेय भी मौजूद रहे।

## किसी में नहीं मिला एनीमिया

ग्रामोदय विवि के आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा यूनिट के प्रभारी डॉ. आरके श्रीवास्तव ने बताया कि इस शिविर में 52 ग्रामीण मरीजो की चिकित्सा की गई, जिसमे 5 महिला, 5 पुरुष एवं 42 बच्चे रहे। इन मरीजों को दवा भी वितरित की गई। किसी भी रोगी में स्किल सेल एनीमिया रोग के लक्षण नहीं मिले। शिविर में जानकीकुंड चिकित्सालय के डॉ. विवेक द्विवेदी, विवि के डॉ.राकेश कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार श्रीवास्तव, विनोद कुमार गुप्ता, काली चरण कौटार्य एवं डीफार्मा व एमबीए ग्रामीण प्रबंधन के द्वितीय, चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र-छात्राओ ने अपनी सेवाएं दी।

### 13 लाख टन यूरिया, 10 लाख टन डीएपी, ढाई लाख टन एनपीके की आपूर्ति होगी

# खरीफ के लिए मिलेगी 25 लाख मीट्रिक टन खाद

### -केंद्र सरकार ने दी सहमति, अब पूरे सीजन में होगी आपूर्ति

### -आठ लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण भी करेगी सरकार

भोपाल। संवाददाता

रबी फसलों की कटाई प्रारंभ होने के साथ ही शिवराज सरकार खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गई है। किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इस बार 13 लाख टन यूरिया, दस लाख टन डीएपी और ढाई लाख टन एनपीके की आपूर्ति पूरे सीजन में केंद्र सरकार करेगी। यह पिछले साल की तुलना में अधिक है। इसके साथ ही सरकार ने अपने स्तर से अतिरिक्त खाद की व्यवस्था भी बनाई है। इसके तहत आठ लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण किया जाएगा। प्रदेश में प्रतिवर्ष सीजन के समय खाद की समस्या सामने आती है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऊपर काफी दबाव भी बनता है, क्योंकि किसानों को 70 प्रतिशत खाद इसी माध्यम से उपलब्ध होती है। इसे देखते हुए सरकार ने इस बार आठ लाख मीट्रिक टन खाद का अग्रिम भंडारण करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार अपने संसाधनों से चार लाख टन यूरिया, तीन लाख टन डीएपी और एक लाख टन कांप्लेक्स खाद का भंडारण करेगी। यह खाद किसानों को बिना ब्याज लिए सीजन प्रारंभ होने से पहले दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार को खरीफ सीजन के लिए खाद आपूर्ति का जो प्रस्ताव भेजा था, उस पर सहमति बन गई है।

## केसरी ने दिखाई सक्रियता

**हाल ही में अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक की। इसमें तय हुआ कि केंद्र सरकार 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 10 लाख मीट्रिक टन डीएपी और ढाई लाख टन एनपीके की आपूर्ति पूरे सीजन में करेगी। पिछले साल 12.16 लाख टन यूरिया, छह लाख तीन हजार टन डीएपी और एक लाख 63 हजार टन एनपीके की आपूर्ति की गई थी।**

## पांच लाख टन खाद का भंडारण

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अभी पांच लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद का भंडारण है। इसमें दो लाख 25 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 70 हजार टन डीएपी, दो लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट और 40 हजार टन एनपीके है। बीते रबी सीजन में किसानों को 16.50 लाख मीट्रिक टन यूरिया, पांच लाख 80 हजार मीट्रिक टन डीएपी, छह लाख 50 हजार मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट और साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन एनपीके की आपूर्ति की गई है।

## मई में पहुंच जाएगी खाद

सहकारी समितियों को खरीफ फसलों की बोवनी प्रारंभ होने के पहले मई में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। आपूर्ति पिछले साल की खपत के आधार पर की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने समितियों से पिछले साल की बिक्री की जानकारी बुलाकर कार्ययोजना बनाई है।

## किसानों का अब बढ़ रहा रुझानः फसलों की बोवनी में रिकॉर्ड बनाएगा नर्मदापुरम हरदा और बैतूल

# नर्मदापुरमः चार लाख हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन बोवनी का लक्ष्य

होशंगाबाद। संवाददाता

नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिले नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल में ग्रीष्मकालीन फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड बन चुका है। अब इस बार पहले से भी ज्यादा बोवनी का प्लान बन गया है। इस बार संभाग में पहले से ज्यादा चने का रकबा बढ़ा है। चने की फसल पकने के साथ ही कटाई की तैयारी हो रही है। अब कटाई के साथ ही ग्रीष्मकालीन बोवनी का चक्र शुरू हो जाएगा। इस कारण मई के आखिरी तक बारिश से पूर्व मूंग की फसल निकल आएगी। नर्मदापुरम संभाग में इस बार तीन लाख 92 हजार 50 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन फसल लेने का प्लान बन चुका है। जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

**संयुक्त संचालक ने तय किया लक्ष्य**- यह लक्ष्य संयुक्त संचालक कृषि के द्वारा हाल ही में प्रस्तावित किया गया। जिसमें सबसे ज्यादा नर्मदापुरम जिले में बोवनी होगी। इसके लिए विभाग के द्वारा मूंग के सर्टीफाइड बीज का इंतजाम किया जा रहा है। नर्मदापुरम में गेहूं और चने की कटाई के बाद मूंग और अन्य तीसरी फसल की बोवनी तेजी से शुरू हो जाएगी।

### नर्मदापुरम जिले का लक्ष्य

इस वर्ष जिले में 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर में मूंग लगाने का लक्ष्य बनाया गया है। इसके अलावा उड़द का लक्ष्य 2 हजार हेक्टेयर का है। इसी के साथ मक्का और चरी लगाने के लिए 350 हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया गया है। यहां पर मूंगफली नहीं लगाई जाती है। इस कारण इसका लक्ष्य तय नहीं किया गया है। इसके अलावा अन्य फसलों में तरबूज की पैदावार भी तीसरी फसल के रूप में खूब ली जाती है।

### हरदा जिले का लक्ष्य

रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं और चना की उपज निकालने के बाद हरदा जिले में तीसरी फसल की बोवनी शुरू होने वाली है। यहां का लक्ष्य एक लाख 35 हजार हेक्टयर तय किया गया है। जिसमें मूंग का लक्ष्य एक लाख 35 हजार है। इस बार मूंगफली, उड़द का लक्ष्य अभी तय नहीं किया गया है। यहां पर मक्का और चरी नहीं लगाई जाती है।

**बैतूल जिले का लक्ष्य**| बैतूल में तीसरी फसल का लक्ष्य 6 हजार 500 हेक्टेयर का है। बीते वर्ष यहां पर 4 हजार हेक्टेयर में मूंग लगाई गई थी। इस वर्ष यहां पर किसानों का रुझान बढ़ रहा है जिसके तहत यहां मूंग का लक्ष्य 6 हजार हेक्टेयर का रखा गया। इसके अलावा मूंगफली का लक्ष्य 100 हेक्टेयर से बढ़ाकर 200 हेक्टेयर किया जा रहा है। चरी और मक्का 200 हेक्टेयर में लगाई जाएगी। गेहूं की कटाई शुरू हो रही है। उसके तुरंत बाद जिनके पास सिंचाई सुविधा है वह मूंग की बोवनी करेंगे।

### मूंग के बीज उपलब्ध कराए प्रशासन

किसान उदय पांडेय, शिवमोहन सिंह, नरेंद्र पटेल, सुदीप पटेल, लखन गौर ने कहा कि पिछले बार जिले ने प्रदेश में सबसे अधिक मूंग की पैदावार का रिकॉर्ड बनाया था। शासन की ओर से अभी से बीज का प्रबंध करना चाहिए जिससे किसानों को परेशान नहीं होना पड़े। इसके अलावा मूंग की फसल में पर्याप्त पानी की जरूरत रहती है। इस पर भी प्रशासन स्तर से ध्यान दिया जाना चाहिए।

बीते वर्ष की तुलना में इस बार ग्रीष्मकालीन फसलों का लक्ष्य बढ़ रहा है। ग्रीष्मकालीन फसलों का संभाग का लक्ष्य तय कर दिया गया है। संभाग में इस बार 3 लाख 92 हजार हेक्टेयर में तीसरी फसल ली जाएगी। जिन किसानों के पास सिंचाई सुविधाएं हैं वे तीसरी फसल के रूप में मूंग उड़द और मक्का आदि लगाते हैं। विभाग की ओर से तीसरी फसल का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

**बीएल बिलैया, संयुक्त संचालक कृषि, नर्मदापुरम**

## जबलपुर सहित प्रदेश के किसान अब अपने खेतों में बिजली भी पैदा कर पाएंगे

**बिजली कंपनियां 25 साल तक 3.07 रु. प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेंगी**

# खेतों में बिजली पैदा करेंगे अब अन्नदाता

जबलपुर। संवाददाता

मध्य प्रदेश के किसान अब अपने खेतों में बिजली भी पैदा कर पाएंगे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश के चुनिंदा 1254 सब-स्टेशनों का चयन किया है। बिजली कंपनियां आवेदकों से 25 साल तक 3.07 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेंगी। चयनीत सब-स्टेशनों के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों के लिए खेतों में सोलर प्लांट लगाने का मौका दिया जा रहा है। इस योजना में करीब 240 मेगावाट की क्षमता के प्लांट लगाए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन चार अप्रैल तक भरे जा सकेंगे।

### पीएम कुसुम योजना

केंद्र सरकार की तरफ से 300 मेगावाट का लक्ष्य नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को दिया गया था। बीते साल कुसुम तीन योजना में किसानों से आवेदन मांगे गए थे। इस योजना में पिछले साल 142 किसानों ने योजना में आवेदन किया था। दस्तावेज और शर्त पूरी नहीं करने की वजह से 107 किसानों का आवेदन निरस्त हो गया था। करीब 35 किसान और डेवलपर के ही 61 मेगावाट के पीपीए हुए थे। अब फिर से विभाग ने करीब 240 मेगावाट के लिए आवेदन बुलाए हैं। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी जमीन चयनीत प्रदेश के 1254 बिजली सब स्टेशन के पांच किलोमीटर के दायरे में हैं। 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक का प्लांट किसान अपनी जमीन में लगा सकेंगे। इससे पैदा बिजली को सब-स्टेशन में भेजी जाएगी। इसमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 592, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 533 और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 129 सब स्टेशन चिन्हित किए गए हैं।

### फिर मिलेगा मौका

नवकरणीय उर्जा विभाग ने कहा कि जो किसान और डेवलपर कुसुम योजना में पहले आवेदन कर चुके हैं और उनके आवेदन निरस्त किए है उन्हें भी इसमें मौका मिलेगा। विभाग ने उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया है। इस योजना में अब तक 142 किसानों ने योजना में आवेदन किया था। 35 किसान अभी 61 मेगावाट के पीपीए में शामिल है।

### सब स्टेशन चिन्हित

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने ऐसे सब स्टेशन चिन्हित किए हैं, जहां बिजली की सप्लाई संभव है उनका लोड कम है। उन इलाकों में सोलर से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग सुनिश्चित होगा, कृषि पंप, इंडस्ट्री आदि संयंत्र में बिजली का उपयोग हो। इसलिए ऐसे सब स्टेशन चिन्हित हुए हैं। इससे किसानों का फायदा होगा।

कुसुम योजना के अंतर्गत किसान और डेवलपर चिन्हित सब स्टेशन के आसपास सोलर प्लांट लगाकर आय का जरिया पैदा कर सकता है। जिन किसानों के पास पर्याप्त राशि नहीं है वो डेवलपर के साथ करार कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

**कर्मवीर शर्मा, प्रबंध संचालक**
**मप्र ऊर्जा विकास निगम**

कुसुम तीन योजना में कई किसानों और डेवलपर के द्वारा दस्तावेज, सुरक्षा निधि नहीं जमा करने की वजह से 235 मेगावाट का करार निरस्त किया है। अब फिर से 240 मेगावाट का नए सिरे से निविदा जारी की जा रही है। कई आवेदकों के दस्तावेज पर्याप्त नहीं थे।

**भुवनेश पटेल, मुख्य अभियंता**
**ऊर्जा विकास निगम**

## किसान-डेवलपर भी कर सकते हैं आवेदन

किसान के पास जमीन नहीं है तो कंपनी बनाकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। कंपनी की नेटवर्थ एक किलोवाट के लिए करोड़ रुपए की होनी चाहिए। एक मेगावाट में 16-20 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है। दो मेगावाट में 32-40 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है। 3.07 रुपए प्रति यूनिट बिजली की खरीदी की जाएगी। अगले 25 साल के लिए बिजली खरीदी का बिजली कंपनी के साथ किसान अथवा कंपनी के साथ करार होगा। एक मेगावाट के लिए 3.5 से 4 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। दो मेगावाट के लिए 7-8 एकड़ जमीन लगेगी। यह सुनिश्चत होगा कि किस तरह का माड्यूल किसान सोलर प्लांट लगा रहा है। डेवलपर यदि किसान से जमीन लेता है तो 30-35 हजार रुपए सालना प्रति एकड़ के हिसाब से किराए पर जमीन लेकर इकाई स्थापित कर सकते हैं। डेवलपर के साथ किसान का अनुबंध होगा।

## मुरैना कृषि केंद्र ने इस तकनीक को बढ़ावा दिया

# सरसों के साथ अब किसान बरसीम की कर रहे बोवनी

मुरैना। संवाददाता

अब तक एक बार में एक ही फसल होती थी, लेकिन खेती से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए मुरैना जिले के कई किसान एक साथ दो-दो फसलें करने लगे हैं। इससे फसलें कीट, बीमारी से बच रही हैं और किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है।

मुरैना आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र ने भी इस तकनीक को बढ़ावा दिया और सरसों की खेती से किसानों की आय दोगुनी करके भी बता दी है। इसके लिए सरसों के खेतों में बरसीम की बोवनी कराई गई। पिछले तीन साल से सरसों के साथ बरसीम की खेती करने वाले किसानों ने केवल सरसों की खेती करने वालों से लगभग दोगुनी आय की। इसलिए इस बार ऐसे किसानों की संख्या बढ़ गई है।

मुरैना जिले के हड़बांसी, साटा, बरौली और लालबांस गांव के दर्जनों किसान सरसों के साथ बरसीम (लूसन) की फसल कर रहे हैं। एक बीघा जमीन में चार से साढ़े चार क्विंटल सरसों निकलती है, जो 7000 से 7500 रुपए क्विंटल के भाव बिकती है। यानी एक बीघा जमीन में 30 से 32 हजार की सरसों पैदा होती है। इसी एक बीघा खेत में डेढ़ से दो क्विंटल बरसीम का बीज पैदा होता है, जिसका भाव 13000 रुपए क्विंटल है। यानी एक बीघा में 18 से 26 हजार तक का बरसीम बीज पैदा हो जाता है। बरसीम बीज की खेती के लिए कोई अलग जमीन नहीं चाहिए।

### आमदनी दोगुनी

किसानों को अतिरिक्त जुताई का खर्च नहीं उठाना पड़ता। बस एक बीघा में 20 से 25 किलो यूरिया और सरसों की कटाई के बाद एक सिंचाई की जरूरत होती है। इस अतिरिक्त खर्च में सरसों के खेतों में सरसों से ज्यादा बरसीम बीज की खेती से आय होती है। इसी तरह मुरैना, अंबाह, पोरसा में सैकड़ों किसान लूसन के साथ धनियां की खेती कर रहे हैं। इससे उनकी आमदनी दोगुनी तक हो गई है।

### कीटो से बचाया

जिन-जिन गांवों में किसानों ने चना के साथ धनियां, बरसीम के साथ धनियां और सरसों के साथ बरसीम की फसल की है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि इन फसलों में किसी भी प्रकार के रोग या कीट का प्रकोप नहीं हुआ। चना की फसल में इल्ली रोग ज्यादा लगता है जो धनिया की खुशबू के कारण नहीं लगा। यानी चना के साथ हुए धना की फसल ने कीटों का प्रकोप खत्म कर दिया। इतना ही नहीं एक बीघा खेत में 10 से 12 हजार के धनिया की पैदावार किसानों को हुई है। चने की फसल भी अच्छी है और उससे भी 15 से 18 हजार तक की आय किसानों को प्रति बीघा पर होगी।

मुरैना जिले में अधिकांश किसान अकेली सरसों की फसल करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत चार गांवों में सरसों के साथ बरसीम की खेती करवाई, जिससे किसानों की आय दोगुनी हुई। इस साल भी इन गांवों में सरसों के साथ बरसीम बीज की खेती हो रही है। इस फसल में कोई अतिरिक्त मेहनत या जमीन नहीं लगती, यह किसानों के लिए अच्छी बात है। बरसीम बीज की मांग भी बहुत है, इसलिए ऊंचे दामों में बिकता है और फसलों में कोई रोग भी नहीं लगता।

**संदीप सिंह तोमर,वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना**

# सुंदरकांड पाठ के साथ भोजपाल महोत्सव मेले का आगाज

**भोपाल।** राजा भोज की नगरी भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर भोजपाल महोत्सव मेले का सुंदरकांड पाठ के साथ रंग-बिरंगे गुब्बारे छोड़कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेला संरक्षक और भाजपा नेता एवं पूर्व महापौर आलोक शर्मा रहे। विशिष्ठ अतिथि गिरीश शर्मा, मेला संयोजक विकास विरानी, सतीश विश्वकर्मा, किसान नेता भगवान सिंह परमार, परमार समाज के अध्यक्ष महेंद्र सिंह परमार, राजेंद्र सिंह यादव, रामबाबू शर्मा, रविंद्र साहू, दीपक गुप्ता बसंत गुप्ता, आनंद नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप लोधी, संजय कुंवर, शैतान सिंह लोधी, राम मंदिर अध्यक्ष रमेश यादव, अशोक सैनी, संतोष शर्मा रहे। मेला अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि विगत 6 वर्षों से मेले का सफल आयोजन

## आकर्षक मंच के साथ आने वाले लोगों के लिए ट्रेडिशनल शेल्फी जोन बना आकर्षण का केंद्र

किया जा रहा है। मेले में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। मेले में आने वाले आगंतुकों को इस बार मेला नए कलेवर में देखने को मिल रहा है। महामंत्री हरीश कुमार राम ने बताया कि मेला परिसर में ग्रामीण परिवेश और ट्रेडिशनल लुक में बनाया जाने वाला भव्य स्वागत द्वारा, आकर्षक मंच के साथ ही आने वाले लोगों के लिए ट्रेडिशनल शेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। मेला में प्रतिदिन विभिन्न प्रदेशों के कलाकार नृत्य-गान सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दे रहे हैं।

### मेले में दिख रही भारतीय संस्कृति की झलक

मेला संयोजक विकास वीरानी ने बताया कि यह मेला सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक आयोजन का पारिवारिक संगम है। यहां भारतीय संस्कृति की झलक आंगतुकों को देखने को मिल रही है। लोगों के मनोरंजन के लिए इस वर्ष और बेहतर प्रयास किए गए हैं। मेला परिसर में पहुंचने वाले युवाओं के लिए ट्रेडिशनल सेल्फी जोन तैयार किया गया है। जहां लोग परिजनों और दोस्तों के साथ सेल्फी लेकर इस पल को यादगार बना रहे हैं। मेला के प्रवेश द्वार को ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। इस मौके पर मेला समिति के वीरेंद्र तिवारी, महेंद्र नामदेव, चन्दन वर्मा, अखिलेश नागर, विनय सिंह, दीपक शर्मा, केश कुमार शाह, सुमित रघुवंशी, मधु भवनानी, शैलेंद्र सिंह जाट, आफताब सिद्दीकी, देवेंद्र चौकसे, इंद्रजीत, गोपाल शर्मा सहित समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।

## खेती-किसानी में छोटे से बदलाव से किसान हर साल कमा रहे लाखों रुपए

# रतलाम के दस हजार किसान

रतलाम। संवाददाता

अधिक समय नहीं हुआ जब विभिन्न मांग को लेकर किसान सड़क पर थे। इस बात की जानकारी कम को है कि मध्यप्रदेश के रतलाम में एक छोटा सा बदलाव करके कुछ किसान लाखों रुपए खेती से कमा रहे हैं। इन किसानों ने परंपरागत खेती के तरीके में बदलाव किया व अब जो किया, उससे ही इनकी कमाई अब पहले के मुकाबले बढ़ गई है। कोरोना काल के बाद आमजन को स्वास्थ्य का महत्व समझ आ गया है। इसके चलते बड़ा बदलाव यह हुआ है कि जिले में रासायनिक खेती के बजाए अन्नदाताओं का रुझान जैविक खेती की तरफ हो गया है। हालांकि यह शुरुआत मात्र है व जिले के 6 लाख किसानों में से करीब फिलहाल 10 हजार किसान ही जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाए हैं। देश में जैविक खेती का बाजार करीब 11 हजार करोड़ का हो गया है। पिछले छह वर्ष में ही एक्सपोर्ट बढ़कर 2 हजार करोड़ से 7 हजार करोड़ रुपए का हो गया है।

**हमेशा नया प्रयोग**- कृषि क्षेत्र में जिले के किसानों ने हमेशा नए प्रयोग का स्वागत किया है। बात चाहे अंगूर की खेती की हो या, स्ट्रॉबेरी, उन्नत जामफल, एप्पल बेर, टमाटर, शिमला मिर्च, गराडू, प्याज, लहसुन, मटर उगाने की बात हो या सोयाबीन, गेहूं, चले की पैदावर की, जिले के किसानों ने रतलाम का नाम रोशन ही किया है। जैविक खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अन्य खेती की तरह भूजल का अधिक दोहन नहीं होता है। मिट्टी को बगैर प्रदूषित किए खेती से आने वाली फसले भी जहरीली नहीं होती है।

### 40 वर्ष पहले से अपनाया

किसानों के अनुसार जिले में सबसे पहले जैविक खेती को दिलीप नगर में मोहनलाल चोरड़िया ने अपनाया था। धीरे-धीरे अन्य ने इनको देखकर जैविक खेती की और कदम बढ़ाए। जैविक खेती के बारे में किसान कहते है कि इससे बड़ा लाभ यह होता है कि वायु से लेकर मिट्टी तो प्रदूषित नहीं होती है। इसके साथ ही रासायनीक खेती से होने वाली बीमारी जैसे मधुमेह, हदय रोग, कैंसर, अस्थि, सांस की समस्या, तंत्रिका रोग, चर्म रोग, प्रजजन से जुड़ी समस्या नहीं होती है।

### दावा-वायु से लेकर मिट्ट तक नहीं हो रही प्रदूषित

| किसान का नाम | रकबा | कितने वर्ष | फसल |
|---|---|---|---|
| राजेंद्रसिंह राठौर | 06 हैक्टेयर | 29 | उड़द, मसूर, तुवर |
| चंद्रभानु चौधरी | 09 हैक्टेयर | 03 | सब्जियां, गेहूं, लहसुन |
| संजय पाटीदार धामेड़ी | 12 हैक्टेयर | 08 | छोला चना, मेथी, सोयाबीन |
| मोहनलाल पिरोदिया | 01 हैक्टेयर | 13 | मूंग, उड़द, जामफल |
| विष्णु पाटीदार राकोंदा | 3 हैक्टेयर | 16 | प्याज, लहसुन, सोयाबीन |
| भंवरसिंह कसारी | 1.75 हैक्टेयर | 08 | सोयाबीन, गेहूं व चना |
| सुनील सराफधामनोद | 6.25 हैक्टेयर | 11 | तुवर, मंगफली, मक्का |
| अंबर जाट डेलनपुर | 06 हैक्टेयर | 04 | सोयाबीन, गेहूं व चना |
| डॉ. सिद्धार्थ सुबेदार | 04 हैक्टेयर | 04 | पपीता, केला, सब्जियां |

बदलते वायुमंडल व बढ़ते प्राकृतिक प्रदूषण में जैविक खेती वक्त की मांग है। रासायनीक खाद से जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही है। उसके बाद कृषकों को रुझान जैविक खेती की तरफ हो रहा है।
-चंद्रभान चौधरी धामनोद, प्रगतिशील किसान आंबा

# केसली के बाद पथरिया में लहलहा रही स्ट्रॉबेरी

अनिल दुबे। सागर

जिले की आबोहवा और मिट्टी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुकूल साबित हो रही है। यही वजह है कि केसली के बाद अब सागर ब्लॉक में भी स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रयोग सफल रहा है। शहर से करीब 4 किमी दूर पथरिया गांव के किसान रवींद्र ठाकुर द्वारा 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है, जो सफल रही है। उनकी स्ट्रॉबेरी अब बाजार में भी बिकने लगी है। गौरतलब है कि पिछले साल केसली में एक किसान द्वारा बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी लगाई गई थी, उसी से प्रेरित होकर यहां पर किसान ने जो प्रयोग किया वह सफल रहा। खास बात यह भी है कि केसली की स्ट्रॉबेरी के मुकाबले पथरिया में किसान की स्ट्रॉबेरी में ज्यादा मिठास है। कृषक रवींद्र ठाकुर और उनके पिता श्रीराम ठाकुर ने बताया अक्टूबर माह में उन्होंने हिमाचल से करीब 10,000 पौधे खरीदे थे। उन्हें यहां पर मल्चिंग और ड्रिप पद्धति से लगाया। एक एकड़ की जगह तैयार करने के लिए सितंबर माह में चार से पांच ट्रॉली गोबर की खाद डाली थी। इसके बाद कुछ अन्य कीटनाशक भी खरीदे हैं, जिनका छिड़काव समय-समय पर करना पड़ता है।

### अप्रैल से बिकने लगेगी

पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से कुछ जानकारी जुटाई और उसके अनुसार उपाय किए जिससे फसल पूरी तरह से बर्बाद होने से बच गई। अप्रैल माह तक स्ट्रॉबेरी बिकने के लिए आ जाएगी। किसान अगर अच्छे से स्ट्रॉबेरी की खेती करें तो इसमें दो लाख रुपए तक की लागत आती है।

### अब बढ़ने लगी डिमांड

रवींद्र ने बताया ड्रिप और मल्चिंग पद्धति से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूं। शहर से लगकर ही स्ट्रॉबेरी मिलने लगी है तो आसपास से डिमांड भी शुरू हो गई। इसका स्वाद भी अच्छा है। जिसके बाद रोजाना स्थानीय स्तर पर ही दो से तीन हजार रुपए की स्ट्रॉबेरी बिक रही है। भोपाल, सागर, इंदौर से लेकर बुंदेलखंड के अन्य जिलों से भी डिमांड आ रही है। उन्होंने बताया कि वे किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी नि:शुल्क देने के लिए तैयार हैं। ताकि इससे जुड़कर लाभ कमा सकें।

## आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में काजू की खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

# काजू की खेती बालाघाट को दिलाएगा नई पहचान

रफी अहमद अंसारी। बालाघाट

राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान केन्द्र, बड़गांव, बालाघाट, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बालाघाट, कृषक कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, बालाघाट, कृषि महाविद्यालय, मुरझड़ फार्म, बालाघाट द्वारा काजू एवं कोको विकास निदेशालय, कोच्चि और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकर, नई दिल्ली के सहयोग से बालाघाट जिले में काजू उत्पादन की संभावनाएं विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद डॉ. बिसेन ने कहा कि किसानों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारी आमदानी कैसे बढ़े। इसके लिए फसल उत्पादन के साथ-साथ फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन आदि को भी अपनाना चाहिए। कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लें उस तकनीकी पर खेती करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काजू एक नगदी फसल है। बालाघाट जिले में इसकी खेती के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही सांसद ने अतिरिक्त आमदानी के लिए मधुमक्खी पालन करने का सुझाव भी दिया। वहीं अपर आयुक्त बागवानी एवं निदेशक, मधुमक्खी पालन बोर्ड, नई दिल्ली डॉ. नवीन पटले ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बैहर विकासखंड में काजू की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। काजू की खेती के अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहें हैं। बालाघाट में इसका उत्पादन बड़े क्षेत्र में लेने की जरूरत है।

### मीठी क्रांति पर कार्यशाला

इधर, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से मधुमक्खी पालन का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले में मधुमक्खी पालन से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि बालाघाट जिले में प्रचुर मात्रा में वन पाए जाते हैं। इस प्राकृतिक संपदा के कारण जिले में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जरूरत इसके दोहन की है। मधुमेह मधुमक्खी पालन से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं और इससे उनकी आय में इजाफा होगा। मधुमक्खी पालन का कार्य घर पर भी किया जा सकता है।

# खंडवा में गेहूं को भरपूर समर्थन

| | |
|---|---|
| 8023 | खंडवा |
| 8128 | पुनासा |
| 4976 | हरसूद |
| 3995 | खालवा |
| 4332 | पंधाना |

## तय समर्थन मूल्य से अधिक कीमत में बिक रहा गेहूं

**खंडवा।** गेहूं की फसल कटाई शुरू होने के साथ ही किसान उपज बेचने के लिए मंडी में पहुंचने लगे हैं। नए गेहूं को मंडी में भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। अच्छे भाव मिलने से स्थिति यह है कि मंडी में गेहूं की उपज लेकर आने वाले किसानों के वाहनों की कतार लग रही है। ऐसे में किसान अपना नंबर लगाने के लिए एक दिन पहले ही मंडी पहुंच रहे हैं। कृषि उपज मंडी में गेहूं की भरपूर आवक हो रही है। छह-सात सौ वाहनों में किसान गेहूं लेकर अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों से यहां पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे से शुरू हुई नीलामी का सिलसिला शाम तक चल रहा है। उपज की नीलामी के बाद तुलाई के लिए वाहनों की कतार लग रही है। मंडी में दो अलग-अलग तौल-कांटे होने के बावजूद किसानों को अपनी उपज की तुलाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस बार मंडी में गेहूं की उपज को अच्छे भाव मिलने से किसान वर्ग खुश हैं। मंडी में गेहूं अधिकतम 2281 रुपए क्विंटल तक बिक चुका है।

**38403**
किसानों ने अब तक कराया है पंजीयन

**29590**
किसानों ने कराया गेहूं के लिए पंजीयन

**19168**
किसानों ने कराया चने के लिए पंजीयन

**02.10**
लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल का रकबा

**02.30**
लाख टन खरीदी का है इस वर्ष लक्ष्य

### सरकार ने पांच दिन और बढ़ाई पंजीयन की तारीख, अब दस मार्च तक होगा

# मप्र में 17 लाख किसानों ने समर्थन पर गेहूं बेचने का कराया पंजीयन

**भोपाल। संवाददाता**

मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 17 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीयन कराने की अंतिम तिथि पांच मार्च थी, लेकिन किसानों की सुविधा को देखते हुए इस पांच दिन बढ़ाकर दस मार्च कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 22 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था। इसमें से 17 लाख किसानों ने उपार्जन केंद्रों पर उपज बेची थी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 17 लाख किसान पंजीयन करा चुके हैं। किसानों से ही गेहूं खरीदना और सही व्यक्ति को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए खसरे के सर्वे नंबर को आधार से लिंक करने की व्यवस्था बनाई है। पोस्ट ऑफिस के साथ समन्वय भी बनाया गया है ताकि किसान को परेशानी न हो।

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रक्रिया में बदलाव के कारण बुजुर्ग, महिला और दिव्यांग किसान आधार से बैंक खाता और खसरे के सर्वे नंबर को लिंक कराने के लिए भटक रहे हैं। इससे साफ है कि सरकार नहीं चाहती है कि उसे समर्थन मूल्य पर सभी पात्र किसानों से गेहूं खरीदना पड़े। यही वजह है कि प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। किसान पहले से खाद-बीज के संकट से परेशान हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को अब तक फसल बीमा नहीं मिला है। फसल बीमा की जो राशि दी गई, उसका समायोजन ऋण में कर लिया।

## अन्नदाताओं की जेब पर सरकार लगाएगी छन्ना

प्रदेश के किसानों की जेब पर इस बार तगड़ा झटका लगने वाला है। यूपी की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने से पहले छन्ना लगवाकर (ग्रेडिंग मशीन) उसकी जांच करेगी। इसके लिए बकायदा किसानों से अधिकतम 20 रुपए प्रति क्विंटल तक चार्ज वसूला जाएगा। यानी यदि एक किसान सरकारी गेहूं खरीदी केंद्र अपना 300 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने जाता है तो उसे छह हजार रुपए अगल से देने पड़ेंगे। राज्य सरकार पहली बार सभी 3,500 खरीदी केंद्रों पर यह व्यवस्था अनिवार्य करने जा रही है। प्रदेश में इस बार 17 लाख किसानों से 128 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करेगी।

## उपार्जन केंद्रो में किसानों को नहीं होगी परेशानी

जबलपुर में गेहूं-धान-चना या अन्य प्रकार की उपज की गुणवत्ता को लेकर अब किसान को परेशान नहीं किया जा सकेगा। इस समस्या से निपटने के लिए शासन की ओर से पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के आधार पर साफ-सफाई एवं उड़ाई की मशीनें लगवाए जाने की योजना है। इस दिशा में बकायदा निविदा का प्रारूप तैयार हो चुका है। ई-टेंडर के माध्यम से निविदा निकाली जाएगी। खेत-खलिहान से गहाई के बाद किसान फसल को लेकर उपार्जन केंद्रों पर पहुंचता है। लेकिन अक्सर देखा जाता रहा है कि उपार्जन केंद्रों पर किसान की फसल को मिट्टी-कचरा या भूसी की वजह से लेने से इंकार कर दिया जाता रहा है। इसके बाद किसान को अनेक तरह से शोषण और परेशानी का शिकार होना पड़ता रहा है।

- पिछले साल प्रदेश में 22 लाख किसानों ने कराया था पंजीयन
- कृषि उपार्जन केंद्रों पर लगेंगी उपज को साफ करने वाली मशीनें

# रूस-यूक्रेन युद्ध से गेहूं के भाव छू रहे आसमान

**इधर,** प्रदेश में आने वाले दिनों में महंगा गेहूं आपके भोजन की थाली का बजट बिगाड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी ताजा युद्ध से ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल के बाद अब गेहूं की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। इंदौर की अनाज मंडी में होने वाली गेहूं की आवक कम हो गई है। इसके पीछे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने का कारण बताया जा रहा है। इसके चलते पिछले तीन दिनों में गेहूं की कीमतों में 300 रुपए का उछाल आया है। कहा जा रहा है कि इस सीजन में गेहूं और भी महंगा हो सकता है। एक्सपोर्ट के लिए बड़ी मात्रा में गेहूं गुजरात के कांडला पोर्ट भेजा जा रहा है। मार्च के पहले हफ्ते के तीन दिन में ही गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हर बार मार्च में गेहूं की आवक शुरू हो जाती है और 15 मार्च के बाद भाव स्थिर होने लगते हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण सभी मंडियों में एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी है। तीन दिन पहले गेहूं की कीमत 1950 थी और 100 रुपए कीमत बढ़ी। दूसरे दिन 100 रुपए बढ़ी और फिर 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते अब गेहूं की कीमत दिन दिन में ही 2200 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है।

- एक्सपोर्ट बढ़ने से 3 दिन में 300 रुपए की तेजी
- गुजरात भेज रहे माल, मंडी में आधी हुई आवक

**आवश्यकता**

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

**जागत गांव हमार**

*कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।*

**संपर्क करें**

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)